3

डॉ. अमिता जोशी ने ग्रहण किया कार्यभार

5

कर्मशील, धैर्यशील और प्रबंधन क्षमता के नेतृत्वकर्ता

8

भारत आर्थिक महाशक्ति बनने के रास्ते पर: हरिवंश

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 17 | प्रति सोमवार, 2 सितंबर 2024 | मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

विष्णु के सुशासन में बदल रही छत्तीसगढ़ के वनांचलों की तस्वीर

जनजातीय वर्ग की अर्थव्यवस्था हो रही मजबूत, 8 माह से सँवर रहा है छत्तीसगढ़

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ में नई सरकार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही वंनाचलों में विकास की रोशनी पहुंचाने, प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए पहल शुरू की है। बस्तर अंचल के अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैम्पों का विस्तार किया जा रहा है। 'नियद नेल्लानार' योजना शुरू की गई है। इस शब्द का आशय 'आपका अच्छा गांव'। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई। 'पीएम जनमन योजना' की तरह इस योजना से कैम्पों के निकट

पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाएं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है। इस पहल का ही परिणाम है कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही राज्य में फिर से विकास के लिए नया वातावरण बना है। साय का मानना है कि लोकतंत्र का मूलमंत्र सुशासन है। सुशासन के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती।

प्रदेश सरकार ने भूमिहीन किसानों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले 05 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने वायदों को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी की। प्रदेश में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती-किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है।

सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर काम करना शुरू किया और मात्र 08 माह में ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिखाया।

कमलनाथ VS शिवराज&मोहन सरकार

प्रदेश सरकार पर चार लाख करोड़ का कर्ज

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का तंज- 'कर्ज़ लो और घी पियो' के सिद्धांत पर चल रही है मोहन सरकार

■ कांग्रेस की ओर से अकेले योद्धा बनकर कमलनाथ ने मोहन सरकार को घेरा ■ जताई दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता

-विजया पाठक

एक कहावत है आदमी को केवल उतना ही पैर पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। लेकिन मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यह बात बिल्कुल उलट साबित हो रही है। दरअसल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के विकास को लेकर लगातार कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन विकास का यह कार्य वे उधार लिये हुए पैसों से कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर मध्यप्रदेश के सिर से कर्ज का यह बोझ कब समाप्त होगा। पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सालों तक 04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज प्रदेश पर छोड़ा है। वहीं, अब मोहन सरकार लगातार कर्ज लेकर प्रदेश के विकास की इबारत लिखने की तैयारी में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आरबीआई और विश्व बैंक प्रदेश की जनता से इन करोड़ों रुपये के उधार का कर्ज वसूल करने के लिये आतुर हो जायेगा। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर भी काफी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कटनी जीआरपी थाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दलित समाज प्रदेश में असुरक्षित है और उन पर काफी अत्याचार हो रहे हैं।

(शेष पेज 2 पर)

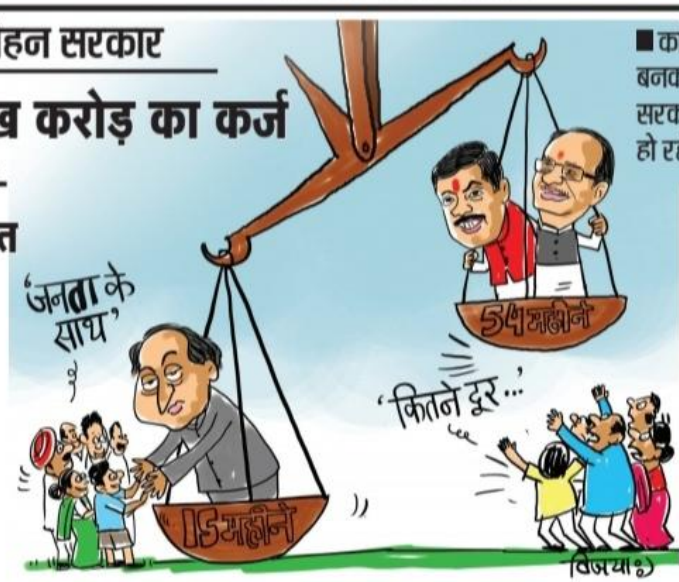

प्रदेश सरकार पर चार लाख करोड़ का कर्ज

(पेज 1 का शेष)

05 हजार करोड़ के लोन की है तैयारी

मध्यप्रदेश में चल रही योजनाओं पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। राज्य सरकार वित्तीय जरूरतें पूरा करने के लिए लगातार बाजार से कर्ज उठा रही है। सरकार एक बार फिर 05 हजार करोड़ का लोन लेने जा रही है। सरकार यह कर्ज दो किश्तों ढाई-ढाई हजार करोड़ के रूप में ले रही है। इसके पहले भी सरकार इसी माह 05 हजार करोड़ का लोन ले चुकी है। प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 03 लाख 75 हजार करोड़ का कर्ज हो चुका है। वित्तीय संकट को देखते हुए वित्त विभाग ने 33 विभागों की 73 योजनाओं पर पाबंदी लगाई है। यानी विभागों को इन योजनाओं पर पैसे खर्च करने के पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। हालांकि वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राशि निकालने से पहले वित्त की मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि योजनाएं बंद हो गई हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को घेरा

भाजपा शासन के समय सबसे ज्यादा कर्ज लेने की बात से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खासे नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के दलदल में धंसती जा रही है। यह कर्ज दो बार में ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के रूप में लिया जाएगा। कर्जखोरी को लेकर कमलनाथ ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। कमलनाथ ने कहा कि 'मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार कर्ज लो और घी पियो के सिद्धांत पर चल रही है। सरकार एक बार फिर से पाँच हज़ार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। प्रदेश पर पहले से ही 3.8 लाख करोड़ का कर्ज है। कमलनाथ ने कहा 'प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबाने वाली भाजपा सरकार के मुंह से आज तक यह नहीं सुना कि अगर प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है तो सरकार फ़िज़ूल ख़र्च में कमी करने के लिए कोई क़दम उठाने जा रही है। लगातार कर्ज लेने के बावजूद न तो प्रदेश में निवेश बढ़ा है, न रोजगार बढ़ा है, न नौकरी बढ़ी है, न ही गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और न ही लाड़ली बहनों को तीन हजार रुपये प्रति महीने दिए जा रहे हैं।

प्रदेश दिवालियेपन की कगार पर न पहुंच जाये

कमलनाथ ने लिखा है कि जब समाज के किसी वर्ग के कल्याण में यह पैसा ख़र्च नहीं हो रहा तो जाहिर है, यह सारा कर्ज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और सत्ता और संगठन मिलकर पैसे की बंदरबांट कर रहे हैं। अगर मोहन यादव सरकार इसी तरह कर्ज लेती रही तो प्रदेश दिवालियेपन की कगार पर पहुँच जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री यादव से कहा कि उन्हें अपनी वित्तीय नीतियों के बारे में फिर से सोचना चाहिए और इस तरह के क़दम उठाने चाहिए जिससे प्रदेश कर्ज के दलदल से बाहर आ सके।

06 अगस्त को लिया था पांच हजार करोड़ का कर्ज

उल्लेखनीय है कि इससे पहले, छह अगस्त को मोहन सरकार ने पांच हजार करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों को राखी के लिए 250 रुपए और 1250 रुपए की मासिक किश्त, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाया एरियर्स की राशि का भुगतान किया गया है। छह अगस्त को लिए गए कर्ज में 11 साल और 21 साल की अवधि में ब्याज का भुगतान करना तय किया गया है। राज्य सरकार औसतन हर महीने 2000 करोड़ का कर्ज ले रही है। इस महीने तो ये दस हजार करोड़ तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले ही चिंताजनक है अब एक और नया कर्ज, एमपी सरकार के वित्तीय संकट के दलदल में फंसने का इशारा कर रहा है।

कमलनाथ की चेतावनी, कब रूकेगा दलितों पर अत्याचार

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कटनी जीआरपी थाना प्रभारी के आफिस में नाबालिग बच्चे और उसकी दादी के साथ हुई मारपीट का वीडियो एक्स पर अपलोड किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जीआरपी थाने में हुई मारपीट बताती है कि मध्यप्रदेश में दलितों पर अत्याचार दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार दलितों के साथ बड़े ही बेरहमी से पेश आ रही है। प्रदेश के दलित अत्याचारों से परेशान हैं।

कैग भी जता चुका है राजकोषीय घाटे पर चिंता

हाल ही में कैग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे पर चिंता जताते हुए कहा था कि सरकार को ज्यादा कर्ज लेने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, नुकसान उठा रहे उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा कर उनमें सुधार की रणनीति बनाई जाना चाहिए। बजट तैयार करने की प्रक्रिया ऐसी हो, ताकि बजट अनुमान और वास्तविक बजट के बीच के अंतर को काम किया जा सके।

इन योजनाओं पर लगाई गई पाबंदी

वित्त विभाग ने जिन 73 योजनाओं पर अनुमति लेना जरूरी किया है, उनमें नगरीय विकास एवं आवास योजना की 08 योजनाएं हैं। इसमें कायाकल्प अभियान, महाकाल परिसर विकास योजना, नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण, एमनी अर्बन डवलपमेंट प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा कृषि विभाग की समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना, ऋण समाधान योजना, औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास, डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश इंवेस्ट ड्राइव, क्लस्टरों की स्थापना, वेदांत पीठ की स्थापना, रामपथ गमन अंचल विकास योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य का नवीनीकरण, लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, मां तुझे प्रणाम, स्टेडियम एवं अधोसंरचना निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन 52 योजनाओं से हटाई गई रोक

वहीं, वित्त विभाग ने 52 योजनाओं से खर्च की पाबंदी को खत्म कर दिया है। जुलाई माह में वित्त विभाग ने 47 विभागों की 125 योजनाओं पर रोक लगाई थी। इसमें से 52 पर रोक हटा ली गई है। बताया जा रहा है कि आरबीआई से कर्ज लेने के बाद इन विभागों से रोक हटा ली गई है। उधर, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सतेन्द्र जैन के मुताबिक "प्रदेश में कोई भी योजना बंद नहीं हुई है। वित्त विभाग की अनुमति लेना वित्तीय अनुशासन की प्रक्रिया होती है। प्रदेश सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। लगातार नई योजनाओं पर काम हो रहा है और पुरानी योजनाओं का भी लाभ लोगों को मिल रहा है।" इधर, कांग्रेस ने सरकार द्वारा लगातार कर्ज लिए जाने को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता आरोप लगाते हैं "सरकार की अधिकांश योजनाएं कर्ज लेकर चल रही हैं।

विष्णु के सुशासन में बदल रही छत्तीसगढ़ के वनांचलों की तस्वीर

(पेज 1 का शेष)

इतने कम समय में जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए यह उनकी प्रशासनिक कुशलता और सफल नेतृत्व का द्योतक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 8 माह की अल्पावधि में कई जन हितकारी फैसलों को समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर जनता की दिन-रात सेवा कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 2 साल के धान का बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित की गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मोदी की इस गारंटी पर त्वरित अमल करते हुए पिछले सरकार के कार्यकाल में राज्य सिविल सेवा परीक्षा (पीएससी) 2021 में हुई गडबड़ी और अनियमितता की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है। राज्य सरकार ने जनहित को देखते हुए महादेव सट्टा एप केस भी सीबीआई को सौंपा। इसके अलावा बेमेतरा जिले के बिरनपुर प्रकरण की भी सीबीआई जांच कराने का भी निर्णय लिया है। विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप श्री रामलला दर्शन योजना शुरूआत की है। भारत में अपने आप में यह एक अनूठी और अनुकरणीय योजना है। इस योजना में श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च में अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ माना गया है। इस कारण वे हमारे लिए और अधिक पूजनीय है। अपने भांचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है।

मुख्यमंत्री साय ने शपथ के कुछ ही घंटो के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए 4 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट रखा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 39 लाख 31 हजार परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया है। इस साल 13 लाख 5 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गइ है। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तरह प्रदेश के 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 01 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नवा रायपुर को आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेशनल केपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह राज्य सरकार भी स्टेट केपिटल रीजन विकसित करने जा रही हैं। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज देंगे 70 लाख महतारी-बहनों को तीजा का उपहार

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 02 सितम्बर को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाले तीजा-पोरा महतारी वंदन तिहार के मौके पर 70 लाख महतारी-बहनों को तीजा पर्व के उपहार स्वरूप महतारी वंदन योजना की सातवीं किश्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री साय इस योजना के तहत माता-बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपए की राशि जारी करेंगे।

महतारी वंदन योजना से सास-बहू की आर्थिक समस्या हुई दूर

कोरबा शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर पहाड़ों से घिरा गाँव है कारीमाटी... पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले इस गाँव में खपरैल वाले कच्चे मकान में एक साथ रहने वाली सास-बहू मंगली बाई और प्रमिला बाई को बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ता है। इनके छोटे से गाँव से अन्य गाँव की दूरी अधिक होने और रास्ते में घना जंगल तथा पहाड़ होने की वजह से रोजी-मजदूरी का काम भी मिल नहीं पाता है। ऐसे में कई जरूरी कार्यों के लिए आर्थिक तंगी के बीच जीवन में भी उदासी थी। महतारी वंदन योजना प्रारंभ होने के बाद नगदी के लिए तरसते सास-बहू को अब खाते में ही हर महीने रुपए मिल जाते हैं, जिससे उन्हें अब जरुरत का सामान खरीदने में कोई परेशानी नहीं आती। हर महीने मिलने वाली महतारी वंदन की राशि इनकी उदासी हटाने के साथ ही खुशियों की वजह भी बन जाती है। कोरबा जिले के दूरस्थ ग्राम कारीमाटी में रहने वाली प्रमिला बाई और उनकी सास मंगली बाई ने बताया कि अन्य गाँवों से उनके गाँव की दूरी अधिक होने की वजह से वे कहीं जा नहीं पाते। गाँव में जो थोड़े बहुत खेत हैं उनमें ही खेती-किसानी में सहयोग कर लेती हैं। गाँव में दूसरी मजदूरी मिलना मुश्किल है। आसपास के गांवों की दूरी इतनी अधिक है कि वे चाहकर भी जा नहीं सकते। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना प्रारंभ होने के समय सास-बहू दोनों ने आवेदन जमा किया था। योजना से जुड़ने के बाद हर महीने उनके बैंक खाते में एक हजार की राशि आती है। इस राशि से घर में किराना सहित अन्य जरूरतों की पूर्ति आसानी से हो पाती है।

मंगली बाई ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा महतारी वंदन योजना शुरू किए जाने पर हम जैसी पहाड़ और वनांचल क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को खुशहाल जीवन का एक आधार मिल गया। ग्रामीण महिलाओं के लिए एक हजार की राशि कोई छोटी रकम नहीं होती। उन्होंने कहा कि वह अपनी बहू के साथ हर महीने बैंक जाकर पैसा निकाल लाती है और इस राशि का उपयोग घर के बहुत जरूरी कार्यों में करती है। (जगत फीचर्स)

डॉ. अमिता जोशी ने प्राचार्य पद पर ग्रहण किया कार्यभार

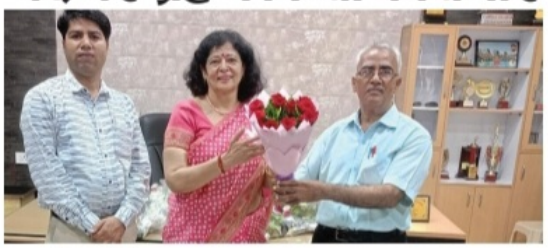

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। शासकीय नर्मदा कॉलेज नर्मदापुरम में प्राचार्य पद पर राजनीति शास्त्र की विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक डॉ. अमिता जोशी ने कार्यभार ग्रहण किया। ज्ञात हो कि पूर्व प्राचार्य डॉ. ओ.एन. चौबे की सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए इस पद पर वरिष्ठता के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने डॉ. जोशी को प्राचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेशित किया था। डॉ. अमिता जोशी 1987 से राजनीति शास्त्र की प्राध्यापक हैं। शास. महाविद्यालय टीकमगढ़ में प्रथम नियुक्ति प्राप्त डॉ. जोशी ने 2006 में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से पी.एच-डी की उपाधि प्राप्त की। उनकी एक पुस्तक, एक रिसर्च प्रोजेक्ट एवं तीस रिसर्च पेपर प्रकशित हो चुके हैं। व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ में संभागीय समन्वयक और युवा उत्सव की जिला समन्वयक रहीं डॉ. जोशी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल और केंद्रीय अध्ययन मंडल की वरिष्ठ सदस्य हैं। छात्र संघ प्रभारी एवं अन्य प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए उन्होंने महाविद्यालय की प्रगति में विशेष योगदान दिया है। उनके प्राचार्य बनने पर महाविद्यालय परिवार ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। (जगत फीचर्स)

सड़कों पर गोवंश, जिम्मेदार डकार रहे आवंटित राशि

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। गोवंश की जो स्थिति नरसिंहपुर जिला में है प्रदेश में कहीं नहीं होगी। यहां सिर्फ नाम मात्र के लिए गोशाला चल रही है। पूरे क्षेत्र में चाहे राष्ट्रीय मार्ग सड़क या राज्यमार्ग सड़कों पूरी सड़कों पर गौमाता दिखाई देगी। जो गोशाला बनी हुई है जो काग़ज़ों पर चल रही हैं। गौमाता के नाम पर जिम्मेदार रकम डकार रहे हैं। शासन के अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की ना तो कभी जांच होती ना तो गोशालाओं को चलाने के लिए उनकी देखरेख के लिए किसी प्रकार की कोई कमेटी बनाई गई। जबकि प्रशासन को कमेटी गठित कर समय-समय पर गोशालाओं की जांच करना चाहिए। रात्रि में शहरों के लोग छोड़ देते हैं। जिससे शहर से लगे किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। शहरों से लगी भूभाग खेत बंजर पड़ी हुई रहती हैं। ऑल इंडिया बेक वर्ड क्लासेस फेडरेशन ने मप्र शासन प्रशासन से मांग और अनुरोध किया है कि इन गोशालाओं का निरीक्षण किया जाए। संचालित गोशालाओं में कमेटी बने जिनकी देखरेख में गोशाला संचालित हो सके। उस कमेटी में सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गांव, शहर के सम्मानित व्यक्ति, रिटायर अधिकारी, कर्मचारी लोग हों। (जगत फीचर्स)

सीएमओ, लेखापाल और इंजीनियर पर आयुक्त ने 21 लाख की रिकवरी का भेजा नोटिस

मामला जीआई पाईप खरीदी का, 39 लाख से खरीदी कर किया था लाखों का भ्रष्टाचार

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर परिषद में आये दिन भारी भ्रष्टाचार को लेकर मामले सामने आये हैं। इसी तरह अब एक ओर बढ़ा मामला सामने आया है। जहां नगर परिषद द्वारा भारी भ्रष्टाचार करते हुए 39 लाख रूपये की लागत से जीआई पाईप की खरीदी की थी जिसमें तत्कालीन सीएमओ राहुल शर्मा, इंजीनियर रितेश यादव एवं प्रभारी लेखापाल केवलराम देवडा पर विभागीय आयुक्त द्वारा 21 लाख रूपये की रिकवरी के नोटिस थमाए गए एवं 23 अगस्त को भोपाल पेशी पर बुलाया गया। 21 लाख रूपये की रिकवरी के नोटिस से नगर परिषद में हड़कंप मच गया है तो वहीं तत्कालीन सीएमओ, इंजीनियर, लेखापाल अब एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं तो वहीं नगर परिषद के अध्यक्ष का नाम भी इस भ्रष्टाचार की लिस्ट में आ सकता है क्योंकि खरीदी तो नगर परिषद के अध्यक्ष ओर पीआईसी के पार्षदों की सहमति से हुई थी और अधिकारीयों पर दबाब बनाकर कर्मचारीयों को मनमाने पद देकर बिल भुगतान कराया गया था।

यह है जीआई पाईप खरीदी का मामला- नगर परिषद द्वारा फरवरी 2023 में शंकर मंदिर से लेकर गांधी चौक ओर इतवारा बाजार चौक तक बनाई गई सीसी सड़क के किनारे पेयजल लाईन डालने के नाम पर 39 लाख रूपये कि लागत से 80 एमएम के 6 मीटर लंबे जीआई पाईप 293 नग खरीदे थे। जो कि एकदम घटिया क्वालिटी के थे। जिसे खातेगांव के एक फर्म से 39 लाख रूपये में खरीदकर लाखों को भ्रष्टाचार किया गया था। जबकि खरीदा गया पाईप बाजार में मात्र 4 हजार रूपये में प्रति पाईप मिल रहा है परंतु नगर परिषद द्वारा 4 हजार रूपये के पाईप को 13 हजार रूपये प्रति पाईप में खरीदा था।

पूर्व अध्यक्ष ने की थी शिकायत- नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने वर्तमान परिषद द्वार जीआई पाईप की खरीदी में किए गए लाखों के भारी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर, संभागीय आयुक्त एवं नगरीय प्रशासन को की थी। जायसवाल ने शिकायत कर बताया था कि वर्तमान नगर परिषद ने जो पाईप खरीदे थे उनका बजन मात्र 36 किलो ही है जबकि बाजार में अच्छी कंपनी के पाईप का बजन 45 किलो आ रहा है जो 4500 में मिल रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद द्वार 36 किलो बजन वाले पाईप को 13 हजार रूपये प्रति नग से खरीद कर जनता के रूप्यों की वर्षादी करना है ओर भारी भ्रष्टाचार कसा है।

इनका कहना है

जीआई पाईप खरीदी के मामले में अभी रिकवरी को लेकर ऐसी कोई जानकारी नहीं है जांच चल रहीं है।
-राहुल शर्मा, तत्कालीन सीएमओ, टिमरनी

जीआई पाईप के मामले में रिकवरी को लेकर नोटिस मिले है, उसी संबंध में भोपाल आया हूँ।
-रितेश यादव, इंजीनियर नपा, टिमरनी

मेरे द्वारा जीआई पाईप के मामले में शिकायत की गई थी जिसकी जांच होकर लगभग 21 लाख रूपये की रिकवरी के नोटिस मिले हैं। इनके उपर एफआईआर दर्ज कराऐ जाने की मांग भी की जा रही है।
-सुभाष जायसवाल, पूर्व नपा अध्यक्ष, टिमरनी
(जगत फीचर्स)

सम्पादकीय

नीति विज्ञान से मिली नवाचारों को मजबूती

दूरगामी प्रभाव वाली एक ऐतिहासिक पहल के रूप में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की बायो ई 3 (अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य स्वच्छ, हरित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के लिए उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यह नीति पूरी दुनिया के भविष्य के आर्थिक विकास के शुरुआती मार्गदर्शकों में से एक के रूप में भारत के लिए वैश्विक परिदृश्य में अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करेगी। भौतिक उपभोग, अत्यधिक संसाधन उपयोग और अपशिष्ट उत्पादन के असंवहनीय प्रारूप ने विभिन्न वैश्विक आपदाओं को जन्म दिया है, जैसे जंगल की आग, ग्लेशियरों का पिघलना और जैव विविधता में कमी आदि। भारत को 'हरित विकास' के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने की राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत बायोई 3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति जलवायु परिवर्तन, घटते गैर-नवीकरणीय संसाधनों और असंवहनीय अपशिष्ट उत्पादन की चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि में, सतत विकास की दिशा में एक सकारात्मक और निर्णायक कदम है। इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रसायन आधारित उद्योगों को अधिक स्थायी जैव-आधारित औद्योगिक मॉडल में परिवर्तित करना है। यह चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा, ताकि नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसके लिए यह जैव-आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए माइक्रोबियल सेल कारखानों द्वारा बायोमास, लैंडफिल, ग्रीन हाउस गैसों जैसे अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा, बायोई 3 नीति भारत की जैव अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने, जैव-आधारित उत्पादों के पैमाने का विस्तार करने और व्यावसायीकरण की सुविधा प्रदान करने, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा कम करने, इनका पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करने, भारत के अत्यधिक कुशल कार्यबल के समूह का विस्तार करने, रोजगार सृजन में तेजी लाने तथा उद्यमिता की गति को तेज करने के लिए अभिनव समाधान तैयार करेगी। नीति की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:1) उच्च मूल्य वाले जैव-आधारित रसायन, बायोपॉलिमर और एंजाइम, स्मार्ट प्रोटीन और फंक्शनल फूड, सटीक जैव चिकित्सा; जलवायु अनुकूल कृषि; कार्बन स्तर में कमी और इसका उपयोग, तथा समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे विषयगत क्षेत्रों में स्वदेशी अनुसंधान और विकास-केंद्रित उद्यमिता को प्रोत्साहन और समर्थन; 2) जैव विनिर्माण सुविधाएं, जैव फाउंड्री क्लस्टर और जैव-कृत्रिम बुद्धिमत्ता (बायो-एआई) हब की स्थापना के जरिये प्रौद्योगिकी विकास और व्यावसायीकरण में तेजी; 3); नैतिक और जैव सुरक्षा विचार पर जोर देते हुए आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के पुनरुत्पादन मॉडल को प्राथमिकता देना; 4) वैश्विक मानकों के अनुरूप नियामक सुधारों का सामंजस्य। यह परिकल्पना की गई है कि जैव-विनिर्माण हब केंद्रीकृत सुविधाओं के रूप में काम करेंगे, जो उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से जैव-आधारित उत्पादों के उत्पादन, विकास और व्यावसायीकरण को गति प्रदान करेंगे। इससे एक ऐसे समुदाय का निर्माण होगा, जहां जैव-विनिर्माण प्रक्रियाओं के पैमाने, स्थायित्व और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संसाधन, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी साझा की जा सकती है। बायोफाउंड्री का तात्पर्य है, उन्नत क्लस्टरों के निर्माण, ताकि जैविक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं को पैमाने के अनुरूप- प्रारंभिक डिजाइन और 'परीक्षण चरणों से लेकर पायलट' तथा 'पूर्व-व्यावसायिक उत्पादन' तक तैयार किया जा सके। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए एमआरएनए-आधारित टीकों और प्रोटीन का बड़े पैमाने पर निर्माण कुछ सराहनीय उदाहरण हैं, जिनके लिए बायोफाउंड्री मूल्यवान हो सकती हैं। ये क्लस्टर मानकीकृत और स्वचालित प्रक्रियाओं का उपयोग करके जैविक प्रणालियों और जीवों के डिजाइन, निर्माण एवं परीक्षण में विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे।

सियासी गहमागहमी

क्या पटवारी के विरोध प्रदर्शन से आएगा बदलाव?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इन दिनों लगातार भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन में जुटे हैं। पटवारी द्वारा किए जा रहे यह प्रदर्शन इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि हैं कि पटवारी पिछले छह महीने से जो शांत बैठे थे उसकी लगातार आलोचना हो रही थी उसके बाद कांग्रेस आलाकमान के भय से पटवारी ने योजनाबद्ध ढंग से भोपाल में लगातार प्रदर्शन कार्यक्रम तैयार किए। अब देखने वाली बात यह है कि पटवारी के यह प्रदर्शन प्रदेश में भाजपा सरकार ने कोई हलचल पैदा कर पाते हैं यह एक बार फिर उन्हे फिर आलोचना का शिकार होना पड़ता है।

हांडी फोड़ चर्चा में आए शिवराज

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। शिवराज सिंह बीते दिनों भोपाल में अपने आवास पर दही हांडी फोड़ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने उन्हें मामा कहकर पुकारा और अपने ही आवास में इतना बड़ा जलसा करने पर प्रदेश के मुखिया की उपाधि फिर दे दी। चर्चा इस बात की भी है कि कई मंत्री और नेता शिवराज के इस आयोजन में दबे पांव शामिल हुए ताकि चौहान को बुरा न लगे। जाहिर है यह वही नेता हैं जो लंबे समय से शिवराज के पीछे घूमते थे और अब मोहन यादव जी के पीछे घूमते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि शिवराज के इस आयोजन पर केंद्रीय नेतृत्व की क्या प्रतिक्रिया होती है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

गुजरात में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन और भयंकर होती जा रही है। इस आपदा में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो प्रभावित लोगों की और राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन की हर संभव सहायता करें।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों का एक ही काम है कि हर चीज को इवेंट बना दिया जाए और बाद में उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए।

प्रदेश में माली बनाने के लिए 2500 युवाओं को ट्रेनिंग तो दे दी गई लेकिन उन्हें रोजगार देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

कर्मशील, धैर्यशील और प्रबंधन क्षमता के नेतृत्वकर्ता हैं कमलनाथ

समता पाठक/जगत प्रवाह

कमलनाथ एक धैर्यशील नेता हैं। प्रशासनिक और प्रबंधन क्षमता के साथ ही विरोधियों को साधने की क्षमता ने उन्हें मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दिया। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का जन्म 18 नवम्बर 1946 को कानपुर, उत्तरप्रदेश में हुआ। कमलनाथ ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से बी.कॉम. तक शिक्षा प्राप्त की। राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता और कृषक कमलनाथ वर्ष 1980 में पहली बार मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिये निर्वाचित हुए। इसके बाद वे वर्ष 1985 में दूसरी बार आठवीं लोकसभा के लिये, वर्ष 1989 में नवीं लोकसभा के लिये तीसरी बार और वर्ष 1991 में दसवीं लोकसभा के लिये छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही चौथी बार निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1991 से 1995 की अवधि में केन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वर्ष 1995-96 में केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे।

वर्ष 1998 में कमलनाथ पुनः छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से पांचवीं बार 12वीं लोकसभा के लिये निर्वाचित हुए। कमलनाथ वर्ष 1998 से 1999 के दौरान पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थाई समिति, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति और विद्युत मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। कमलनाथ वर्ष 1999 में छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही 13वीं लोकसभा के लिये छठवीं बार निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1999 से वर्ष 2000 की अवधि में वित्त संबंधी स्थाई समिति के सदस्य और वर्ष 2002-2004 की अवधि में खान और खनिज मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

कमलनाथ वर्ष 2001 से 2004 की अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे और वर्ष 2004 में सातवीं बार 14वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने 23 मई, 2004 से वर्ष 2009 की अवधि में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का दायित्व संभाला। वे वर्ष 2009 में छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही आठवीं बार 15वीं लोकसभा के लिये पुनः निर्वाचित हुए और वर्ष 2009 से 18 जनवरी, 2011 की अवधि में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहे। (शेष पेज 7 पर)

घटते जंगल और कटते पेड़ कहीं विनाश का संकेत तो नही

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा

पर्यावरणविद्

जगत प्रवाह. भोपाल।

पेड़ों के हो रहे बेतहास कटान से एक तरफ सांस लेने योग्य शुद्ध हवा की कमी महसूस की जा रही है। वहीं बढ़ते प्रदूषण ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भयावह रूप अख्तियार कर चुकी है। वर्तमान में कृषि भूमि, गोचरान, नदी नालों के किनारों से हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से सभी भली भांति परिचित हैं। पेड़ों की अत्याधिक कटाई व उनके अवैध व्यापार से जंगलों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते वन सम्पदा नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। साथ ही राष्ट्रीय पार्कों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मौजूदा हालात गवाह है कि अब जंगलों में विलायती बबूल के अलावा वन सम्पदा दिखाई नही देती है। दूसरी तरफ वन्य जीवों के आवास खत्म होते जाने से उनका जंगलों में रहना मुश्किल हो रहा है। यही नही पेड़ों के कटान से वर्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आज के युग में, जब दुनिया तकनीकी उन्नति और आर्थिक विकास की ओर तेजी से अग्रसर है, तब प्रकृति के साथ हमारा संतुलन

बुरी तरह से बिगड़ता जा रहा है। विशेष रूप से जंगलों का कटान और पेड़ों का विनाश एक गंभीर समस्या बन गया है। यह संकट केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य के लिए भी एक भयंकर चुनौती बन चुका है। जंगल, धरती के फेफड़े माने जाते हैं। ये न केवल वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों और जंगलों के बिना, पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। ये पेड़-पौधे न केवल हमें शुद्ध हवा देते हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में योगदान देते हैं। औषधीय पौधों से लेकर लकड़ी और कागज तक, पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इसके अलावा, जंगलों का संरक्षण वन्य जीवन की विविधता और जैविक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। विश्व भर में लाखों प्रजातियां जंगलों पर निर्भर करती हैं और इनका विनाश सीधे तौर पर इन प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा डालता है। जब एक जंगल काटा जाता है, तो उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। वन्य जीवों का आश्रय छिन जाता है और उनके लिए भोजन के स्रोत भी समाप्त हो जाते हैं। इससे कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है, जो वैश्विक जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

(शेष पेज 7 पर)

बाढ़ और अतिवृष्टि से जूझते लोगों की समस्या का निदान जरूरी

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

जगत प्रवाह. भोपाल।

समूचा आज विकास की ऐसी चादर ओढ़े हुए है कि वह इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ है कि अगर देश में पर्यावरण संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाला समय कितना भयानक होगा। कुछ दिनों की बारिश में जब देश के कई राज्यों में जलभराव की स्थिति बन जाती है तो जरा सोचिए कि जब हर जगह निर्माण कार्य हो जायेंगे और कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। यह सोचकर भी मन घबराता है। क्योंकि पिछले दिनों मध्यप्रदेश ने जो बारिश का दौर देखा है उसे देखने के बाद यह लगने लगा है कि प्रदेश सहित समूचे देश में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और पानी की निकासी को लेकर प्लानिंग के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट के भरोसे चीजों को नहीं छोड़ा जा सकता। इसे लेकर प्री प्लानिंग जरूरी है, तभी हम आमजन और मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश की आबादी को सुविधा दे सकते हैं। अतिवृष्टि और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियाँ पूरी तरह से करें। इसके साथ ही बाँधों में वर्षा जल के अधिक भराव को नहरों में छोड़कर फसल उगाने वाले किसानों के खेतों तक भी पानी पहुँचाना व्यर्थ पानी बहाने का अच्छा विकल्प हो सकता है। वर्षा जल संरक्षण पर वन, ग्रामीण विकास, जल-संसाधन विभाग समन्वित कार्य-योजना बनायें। कार्य-योजना ऐसी हो, जिसमें अतिवृष्टि से बाढ़ से बचाव के साथ-साथ वर्षा जल का उपयोग और संरक्षण भी किया जा सके। वर्षा जल संरक्षण महत्वपूर्ण कार्य है।

प्राकृतिक विपदाओं पर तेज प्रतिक्रिया के लिए सम्यक योजना और उसे लागू करने वाला ढांचा जरूरी है। त्वरित राहत के अतिरिक्त पुनर्वास का काम सुदृढ़ और पारदर्शी होना चाहिए और नुकसान को कम से कम करने की सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार रहनी चाहिए। दीर्घ अवधि के उपाय भी महत्वपूर्ण हैं। जंगल न काटे जाएं, सड़क निर्माण में प्राकृतिक संतुलन का ख्याल रखा जाए, शहरीकरण को पर्यावरणीय संतुलन के साथ चलाया जाए, कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए उद्योगों, बिजली संयंत्रों, रिफाइनरियों, और कार्बन उत्सर्जित करने वाले अन्य उपक्रमों, उद्यमों को लेकर एक नीति बने। नागरिक भागीदारी बढ़ाई जाए। वृक्षारोपण को एक दिन का नारा बनाने के बजाय एक ठोस लक्ष्य बनाया जाए। कानून कड़े और सजाओं का प्रावधान हो। भूजल संग्रहण के साथ-साथ पानी की बर्बादी रोकने के उपाय भी किए जाने चाहिए। वाहनों की आमद और प्रदूषण के लिए बाध्यकारी उपाय चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दशा सुधारनी होगी। सार्वजनिक सेवाओं का इतना निजीकरण एक बेकाबू फिसलन है। जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के रूप में, प्रकृति अपनी अतिशयता और कोप दिखा रही है।

भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएँ बाढ़ की हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा ऋतु के चार महीनों में भारी जलप्रवाह है, परंतु भारत की असम्मित भू-आकृतिक विशेषताएँ विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की प्रकृति तथा तीव्रता के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। बाढ़ के कारण समाज का सबसे गरीब तबका प्रभावित होता है। बाढ़ जान-माल की क्षति के साथ-साथ प्रकृति को भी हानि पहुँचती है। अतः सतत् विकास के नजरिये से बाढ़ के आकलन की जरूरत है। सामान्यतः भारी वर्षा के बाद जब प्राकृतिक जल संग्रहण स्रोतों/मार्गों की जल धारण करने की क्षमता का संपूर्ण दोहन हो जाता है, तो पानी उन स्रोतों से निकलकर आस-पास की सूखी भूमि को डूबा देता है लेकिन बाढ़ हमेशा भारी बारिश के कारण नहीं आती है, बल्कि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही कारणों का परिणाम है। बाढ़ का पानी संक्रमण को अपने साथ लाता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ, जैसे- हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस एवं अन्य दूषित जलजनित बीमारियाँ फैल जाती हैं। बाढ़ की स्थिति इसे और अधिक हानिकारक बना सकती है।

असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश (मैदानी क्षेत्र) और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात एवं हरियाणा में बार-बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मध्यप्रदेश के धार में कारम डैम में हमने गंभीर हालातों को देखा। देश में असम में बाढ़ हो या हिमाचल में अतिवृष्टि हर जगह सरकारी प्रबंधन बौने नजर आते हैं। बाढ़ से बचने के लिए इस बारे में गंभीरता से सोचना जरूरी है, बारिश पूर्व और अतिवृष्टि के क्षेत्रों में शासन-प्रशासन को अधिक मुस्तैदी से आंकलन कराने की जरूरत है। (जगत फीचर्स)

बाढ़ की चपेट में बांग्लादेश भारत को दे रहा दोष

-प्रमोद भार्गव

मुस्लिम देश पाकिस्तान हो या बांग्लादेश सांप्रदायिक सोच की गिरफ्त में इतने हैं कि भारत पर कैसे आक्षेप लगाए जाएं, इसका अवसर तलाशने में लगे रहते है। भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में कुछ ताकतें पूरा जोर लगा रही हैं। पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में मिली शरण को लेकर तो अब बांग्लादेश में आई बाढ़ के पीछे भारत की भूमिका इतनी उग्रता के साथ बताई गई कि सीमा पर भारतीय सैन्य बलों की तरफ से गोलीबारी की अफवाहें तक सोशल मीडिया पर फैला दी गई। इसे लेकर वहां रह रहे हिंदुओं में तनाव इतना बढ़ गया कि ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने जब अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की तो यह अफवाह भी उड़ा दी गई कि उच्चायुक्त को तलब किया गया है। आखिरकार भारतीय विदेश मंत्रालय को दो बार आगे आकर अफवाहों का खंडन करना पड़ गया।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत के इलाके में स्थित बांध के द्वार खोलने की वजह से बांग्लादेश में बाढ़ के हालात बदतर नहीं हुए हैं। दरअसल वहां के मीडिया ने यह सूचना दे दी की भारत में त्रिपुरी के गुमती नदी पर बने दुम्बुर बांध के द्वार खोल दिए गए है, जिससे बांग्लादेश के पूर्वी इलाके में बाढ़ आ गई। जबकि तथ्यात्मक सच्चाई यह है कि बांग्लादेश के जिस क्षेत्र में बाढ़ आई हुई हैं, वहां से दुम्बुर बांध की दूरी 120 किमी से भी ज्यादा है। यही नहीं यहां जो बिजली बनाई जाती है, उसमें से 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को दी जाती है। भारत इस पूरे इलाके में नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी करता है। 21 अगस्त के बाद जो मूसलाधार बारिश त्रिपुरा और इस नदी के जल संग्रह क्षेत्र में हुई है, उसकी सूचना निरंतर बांग्लादेश को दी जाती रही है। 21 अगस्त 2024 को शाम तीन बजे भी सूचना दे दी गई थी। इस क्षेत्र में विडंबना यह भी है कि भारत व बांग्लादेश के आर-पार जाने वाली 54 नदियां हैं। इन पर द्विपक्षीय संबंधों में नदियों के जल बंटवारें की भी बड़ी अहमियत है। तीस्ता नदी के जल बंटवारें को लेकर भी कई बार शेख हसीना से द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं, लेकिन परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। इन सब कारणों के संदर्भ में विदेश मंत्रालय का कहना है कि 'यह बिल्कुल गलत है कि बाढ़ नदी के द्वार खोलने की वजह से आई है। बाढ़ दोनों देशों के बीच एक साझा समस्या है, इससे दोनों देषों की जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। अतएव हर साल पैदा होने वाली इस समस्या से छुटकारे के लिए आपसी सहयोग से काम लेना होगा।'

भारी बारिश के चलते पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में भीषण बारिश से ज्यादातर नदियां बाढ़ के पानी से लबालब है। 1900 जगह भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते 17 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और करीब एक दर्जन लोग मारे गए हैं। हजारों लोगों को 330 राहत शिविरों में षरण दी गई है। भूस्खलन से अनेक जगह सड़क संपर्क बाधित हो गया है। पश्चिमी त्रिपुरा और सिपाहीजला जिला सर्वाधिक बाढ़ की चपेट में है। त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल और कोलासिब का भी बुरा हाल है। सेना और एनडीआरएफ लगातार पानी में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। असम रायफल्स की चार टुकड़ियां इस काम में लगी हुई हैं। अतएव भारत खुद बाढ़ की चपेट में हैं। इस बाढ़ का प्रमुख कारण बांध के नीचे की ओर बढ़े जलग्रहण क्षेत्रों में पानी भर जाने के कारण आई है। वैसे भी दुम्बुर बांध 30 मीटर से भी कम ऊंचाई का बांध है। अतएव बांध की जलग्रहण क्षमता बहुत अधिक नहीं है। बांग्लादेष में बाढ़ से हालात खराब होने का एक बड़ा कारण वहां की सेना और राहत दलों द्वारा व्यापक पैमाने पर कोई कदम नहीं उठाना भी रहा है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। अंतरिम सरकार की तरफ से बार-बार निर्देष जारी किए जाने के बावजूद ढाका व कुछ शहरों के ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर पुलिस थाने अभी भी खाली पड़े हुए हैं। भीड़ का निषाना बनने के डर से पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। ऐसी विषम स्थिति में भारतीय उच्चायुक्त भी अपने कार्यालय और परिसंपत्तियों को बचाने की चिंता में है। जबकि यह मुद्दा प्रणय वर्मा महोम्मद यूनुस के समक्ष उठा चुके है। साफ है, यूनुस ने भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बताकर स्थानीय कट्टरपंथियों को नसीहत जरूर दी है, लेकिन भारत विरोधी अराजक तत्वों पर लगाम लगाने में अंतरिम सरकार सफल होते नहीं दिख रही है। इससे यह भी आशंका होती है कि जब भारतीय उच्चायुक्त ही संकट में है। तो इस बात पर कैसे संतोष कर लिया जाए कि वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित और भयमुक्त हैं?

भारत एवं बांग्लादेश के बीच बहने वाली नदियों के जल बंटवारे को लेकर समझौते की बातचीत 25 वर्ष से चल रही है। शेख हसीना और नरेंद्र मोदी की 2022 में परस्पर हुई बातचीत के बाद कृशियारा नदी के संदर्भ में अंतरिम जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। 1996 में गंगा नदी जल-संधि के बाद इस तरह का यह पहला समझौता है। इसे अत्यंत महत्वपूर्ण समझौता माना गया है। यह भारत के असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र को लाभान्वित करेगा। 54 नदियां भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के आरपार जाती हैं और सदियों से दोनों देशों के करोड़ों लोगों की आजीविका का मुख्य साधन बनी हुई हैं। इन नदियों के किनारों पर मानव सभ्यता के विकास के साथ सृजित हुए लोक गीत और लोक कथाएं, धर्म एवं संस्कृति की ऐसी धरोहर हैं ,जो मानव समुदायों को लोक कल्याण का पाठ पढ़ाने के साथ नैतिक बल मजबूत बनायें रखने का काम करती हैं। बावजूद दोनों देशों के बीच बहने वाली तीस्ता नदी के जल बंटवारे को अंतिम रूप अब तक नहीं दिया जा सका है।

नदियों के जल-बंटवारे का विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद का विषय बना रहा है। ब्रह्मपुत्र को लेकर चीन से, तीस्ता का बांग्लादेश से, झेलम, सतलुज तथा सिंधु का पाकिस्तान से और कोसी को लेकर नेपाल से विरोधाभास कायम है। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में खटास सीमाई क्षेत्र में कुछ भूखंडों, मानव-बस्तियों और तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर पैदा होता रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच संपन्न हुए भू-सीमा समझौते के जरिए इस विवाद पर तो कमोबेस विराम लग गया, लेकिन तीस्ता की उलझन बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में बांग्लादेश यात्रा पर गए थे, तब ढाका में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी, लेकिन तीस्ता की उलझन, सुलझ नहीं पाई थी।

तीस्ता के उद्गम स्रोत पूर्वी हिमालय में स्थित सिक्किम राज्य के झरने हैं। ये झरने एकत्रित होकर नदी के रूप में बदल जाते हैं। नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसलिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पानी से जुड़े हित इस नदी से गहरा संबंध रखते हैं। तीस्ता नदी सिक्किम राज्य के लगभग समूचे मैदानी क्षेत्रों में बहती हुई बंग्लादेश की सीमा में करीब 2800 वर्ग किमी क्षेत्र मे बहती है। नतीजतन इन क्षेत्रों के रहवासियों के लिए तीस्ता का जल आजीविका के लिए वरदान बना हुआ है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के लिए भी यह नदी बांग्लादेश के बराबर ही महत्व रखती है। बंगाल के छह जिलों में तो इस नदी की जलधारा को जीवन-रेखा माना जाता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत इस देश के अस्तित्व में आने के वर्ष 1971 में ही हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से अलग होने वाले स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी और इस देश को पाक की गुलामी से मुक्त कराया। इस कारण दोनों देशों के बीच भावनात्मक संबंध हिंदुओं पर अत्याचार के बावजूद कायम हैं। 1983 में दोनों देशों के बीच एक तदर्थ जल हिस्सेदारी पर संधि हुई थी, जिसके तहत 39 एवं 36 प्रतिशत जल बंटवारा तय हुआ। इस समझौते द्वारा तीस्ता नदी के जल वितरण का समान आवंटन का प्रस्ताव ही नई द्विपक्षीय संधियों का अब तक आधार बना हुआ है। यदि तीस्ता समेत अन्य नदियों पर जल बंटवारें के समझौते हो जाते हैं तो बाढ़ की समस्या स्थायी हल बन सकती है।

(जगत फीचर्स)

छत्तीसगढ़ में 6 IAS अफसरों के डिपार्टमेंट बदले, 4 IPS को अलग-अलग जिलों में मिली पोस्टिंग

हिमशिखर गुप्ता गृह, जेल सचिव बनाए गए

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 IAS अफसरों के विभागों में बदलाव किया है। हिमशिखर गुप्ता को गृह और जेल विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। निहारिका बारिक को महानिदेशक ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। आर प्रसन्ना को ग्रामीण विकास संस्थान और सचिव गृह एवं जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। चंदन कुमार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक का प्रभार दिया गया है। राजेंद्र कुमार कटारा को पाठ्यपुस्तक निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कुलदीप शर्मा को सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार की पोस्टिंग मिली है। इससे पहले 4 IPS अफसरों को अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग दी गई।

4 IPS अफसरों को मिली पोस्टिंग

छत्तीसगढ़ कैडर के 4 IPS अफसरों को राज्य सरकार ने अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग दी है। इन अधिकारियों ने अपने सेकंड राउंड की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब ये नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसे लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक आकाश श्रीमाल CSP जगदलपुर, अजय कुमार CSP सिविल लाइन रायपुर, अक्षय प्रमोद CSP बिलासपुर और विमल कुमार पाठक CSP दर्री कोरबा की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरह आईएएस कुलदीप शर्मा (2014), प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम एवं अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन तथा रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं के पद पर पदस्थ किया गया है। भा.प्र.से. राजेन्द्र कुमार कटारा (2013), संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन, (CG IAS Latest Transfer List August 2024) मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को उनके वर्तमान प्रभारों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हिमशिखर गुप्ता (2007), सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को उनके वर्तमान प्रभारों के साथ-साथ सचिव, गृह एवं जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस चंदन कुमार (2011), विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके वर्तमान प्रभारों के साथ-साथ नियंत्रक खाद्य एवं औषधी प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। (जगत फीचर्स)

अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर

भू-माफियाओं के कब्जे से खाली करवाई गई सरकारी जमीन

-संवाददाता

जगत प्रवाह. राजिम। राजिम में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार बुलडोजर लेकर धान खरीदी केंद्र के सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंचे। यह पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई है।

भू-माफियाओं ने किया था सरकारी जमीन पर कब्जा

बता दें कि, भू-माफियाओं ने धान खरीदी केंद्र की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की जा रही है।

तहसीलदार ने दी कार्रवाई की जानकारी

इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए तहसीलदार ने बताया कि, कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। (जगत फीचर्स)

बहेरिया पुलिस ने चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार, 85 हजार रूपये के सोने-चांदी के जेवरात बरामद

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. सागर। बहेरिया पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फरियादी रघुनाथ पटेल पिता सीताराम थाना बहेरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई अज्ञात आरोपी दिनाँक 24.8.24 की रात्रि मे इनके घर मे घुसकर पेटी मे रखे सोने चांदी के जेवरात करीबन 85000 रूपये के चोरी कर ले गया कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 297/24 धारा 331 (4), 305 (ए) BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान फरियादी गवाहों के कथन लेख किये गये जिनके द्वारा गाँव के कलू पटैल पर संदेह होना लेख कराया गया जिसके आधार पर लगातार मुखबिरों से संपर्क कर संदेही कलू उर्फ रामचरण पटैल पिता मुन्ना उर्फ खुमान पटैल निवासी नरवानी थाना बहेरिया को दिनाँक 28.8.24 को दस्तयाब कर चोरी गया मसरूका एक सोने का मंगल सूत्र, एक सोने का हार, चादी की चूडियाँ, बिछिया, पायले कीमती करीबन 85000 रूपये की तथा घटना में प्रयुक्त लोहे राड आदि विधिवत जप्त किया गया एवं आरोपी की गिरफ्तारी की गई। जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सागर, अति. पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहेरिया उनि आदिल खान, प्रआर 30 कैलाश विश्वकर्मा, प्रआर 181 दिनेश राजपूत, प्रआर 792 मनोज मिश्रा, आर 454 प्रहलाद, आर 680 शुभम सेंगर का सराहनीय योगदान रहा। (जगत फीचर्स)

कर्मशील, धैर्यशील और प्रबंधन क्षमता के नेतृत्वकर्ता हैं कमलनाथ

(पेज 5 का शेष)

इसके बाद वे 19 जनवरी 2011 से 26 मई 2014 की अवधि में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री और 28 अक्टूबर 2012 से 26 मई 2014 की अवधि के लिये केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। कमलनाथ मई, 2014 में छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही नवमीं बार 16वीं लोकसभा के लिये पुनः निर्वाचित हुए। कमलनाथ को 4 से 6 जून, 2014 की अवधि में लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। वे एक सितम्बर, 2014 से संसद की वाणिज्य संबंधी स्थाई समिति और वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

कमलनाथ की प्रकाशित पुस्तकों में इण्डियाज एनवायरनमेंटल कंसर्न्स, इण्डियाज सेंचुरी और भारत की शताब्दी, प्रमुख हैं। उन्होंने जनजातीय और दलित वर्गों का विकास, वन्य-जीव, बागवानी, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों में विशेष अभिरुचि है। इसके अलावा कमलनाथ कोलकाता क्रिकेट और फुटबाल क्लब, टॉलीगंज क्लब कोलकाता, दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सदस्य और एक्स चीफ पैट्रन, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य रहे हैं।

कमलनाथ ने अनेक देशों की यात्राएं की हैं। वे वर्ष 1982, 1983 में संयुक्त राष्ट्र गए भारतीय शिष्ट मंडल के सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1983 में गुटनिपेक्ष देशों के सम्मेलन, वर्ष 1987 में आईपीयू सम्मेलन, निकारागुआ, वर्ष 1988 में ग्वाटेमाल और वर्ष 1990 में साइप्रस में भाग लिया। वे वर्ष 1989 में टोक्यो में, वर्ष 1989 में साइप्रस और 1990 में यूनाइटेड किंगडम गये शिष्ट मंडल में शामिल रहे। वर्ष 1990 में पेरिस में दसवें विश्व वानिकी सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मंडल के नेता रहे। वर्ष 1991 में वे यूएनईपी शासी परिषद, नैरोबी, प्रेपकाम-चार पर विचार-विमर्श, न्यूयार्क और क्वालालमपुर सम्मेलन में शामिल हुए।

पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नाथ ने पारिस्थितिकीय संरक्षण और प्रदूषण उपशमन संबंधी राष्ट्रीय नीति का प्रतिज्ञापन और विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाथ की नीतिगत पहलों में पर्यावरण अधिकरण की स्थापना, पर्यावरण परीक्षा (ऑडिट) की अवधारणा, वन्य-जीव-प्राणी-जगत और वनस्पति-जगत संरक्षण और सुरक्षा हेतु कदम और पर्यावरण ब्रिगेडों और वनीकरण ब्रिग्रेडों का गठन (उनके नेतृत्व में वनीकरण और भारत में अक्रमित भूमि के विकास का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया), पर्यावरण टैरिफ की वैश्विक अवधारणा का प्रतिज्ञापन और वैश्विक उत्सर्जन कोटे की अवधारणा का प्रतिपादन शामिल है। कमलनाथ वर्ष 2018 में 26 अप्रैल को मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। कमलनाथ को 14 दिसम्बर, 2018 को मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया। उन्होंने 17 दिसम्बर 2018 को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

घटते जंगल और कटते पेड़ कहीं विनाश का संकेत तो नही

(पेज 5 का शेष)

जंगलों के घटते क्षेत्रफल का प्रभाव न केवल स्थानीय स्तर पर महसूस किया जा रहा है, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारणों में से एक जंगलों की कटाई है। जब पेड़ काटे जाते हैं, तो वे अपने अंदर संग्रहीत कार्बन को मुक्त कर देते हैं, जो वातावरण में जाकर ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को बढ़ाता है। यह तापमान में वृद्धि का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना और अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

इसके साथ ही, जंगलों का कटान और पेड़ों का विनाश भी जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पेड़ और वनस्पतियाँ वर्षा जल को अवशोषित करके उसे भूमिगत जल के स्रोतों में संग्रहीत करने में मदद करती हैं। लेकिन जब ये पेड़ काटे जाते हैं, तो जल संचय की यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे जल संकट की समस्या बढ़ जाती है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण कृषि और पेयजल की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिससे स्थानीय आबादी की आजीविका पर गहरा असर पड़ रहा है। मानव गतिविधियों, जैसे कि खेती, उद्योग और शहरीकरण के चलते जंगलों की कटाई हो रही है। बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के विस्तार, लकड़ी की मांग और शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने जंगलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। विशेष रूप से विकासशील देशों में, जहां आर्थिक प्रगति की दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, वहाँ जंगलों का विनाश तेजी से हो रहा है। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब स्थानीय समुदायों और आदिवासी जनजातियों का जीवन और संस्कृति सीधे तौर पर जंगलों पर निर्भर होता है। जंगलों के बिना ये समुदाय अपनी पारंपरिक जीवनशैली को खोने के साथ-साथ अपनी पहचान और आजीविका को भी खो देते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। सबसे पहले हमें जंगलों के संरक्षण और पुनर्स्थापन पर जोर देना होगा। वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और नई तकनीकों का उपयोग करके जंगलों के कटान को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा, स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें जंगलों के संरक्षण में शामिल करना आवश्यक है। साथ ही, सरकारों को सख्त नियम और कानून बनाकर, जंगलों की कटाई पर नियंत्रण लगाना होगा, और उन कंपनियों और व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करनी होगी जो अवैध रूप से जंगलों को काटते हैं।

प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यदि हम अब भी नहीं चेते और अपने जंगलों और पेड़ों को संरक्षित करने के लिए कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण न केवल हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी हमारी नहीं, बल्कि हम पृथ्वी के हैं। इसलिए, इस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए हमें आज और अभी से कार्य करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में जीवन जी सकें।

कलम के सिपाही...

अतुल श्रीवास्तवः पत्रकारिता में रहा अतुलनीय योगदान

-भूपेन्द्र निगम

भोपाल में लगभग दो दशक तक सक्रिय पत्रकारिता करने वाले अतुल श्रीवास्तव के इस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान को कतई नहीं भुलाया जा सकता। समाचार-पत्रों में व्यापार रिपोर्टिंग को उन्होंने कई नये आयाम दिये। दैनिक मध्यदेश से उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरूआत 1969 के आसपास की थी। बाद में वे देशबन्धु में रिपोर्टर रहे और 1974 में दैनिक भास्कर भोपाल में आए। तब श्याम सुन्दर ब्यौहार भास्कर के सम्पादक हुआ करते थे। दैनिक भास्कर इन दिनों अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा था। अतुलजी के पास रिपोर्टिंग के कार्य के साथ शुरूआत से ही व्यापार पृष्ठ की मुख्य जिम्मेदारी रही। नई दुनिया इन्दौर उस समय शबाब पर था। व्यापार जगत का सबसे अच्छा कवरेज नई दुनिया ही किया करता था। ऐसे में उनके समक्ष एक विशेष चुनौती थी। किसी भी चुनौती को सहर्ष स्वीकार करने वाले और धुनी स्वभाव के अतुलजी को एक सहयोगी गंगाप्रसाद दुबेजी भी दिये गये थे। उन दिनों संचार सुविधाओं का ऐसा विकास नहीं हो पाया था जो आज मीडिया के पास है। ऐसे में अपने काम को अंजाम देने में हरेक रिपोर्टर को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। वेतन-भत्ते भी आज की तुलना में बेहद कम थे। मगर धाकड़ों के बीच अपने आपको सिद्ध करने की जबरदस्त जद्दोजहद आज से भी अधिक थी। चूंकि नई दुनिया का प्रकाशन स्थल इन्दौर था और प्रदेश का बाजार वहीं से चलता था, लिहाजा रिपोर्टर को वह दिक्कत नहीं आती थी जो भोपाल में बैठे प्रतिनिधि को झेलना पड़ती थी। अतुलजी ने ऐसे पॉकिट्स तलाशे जो उन्हें व्यापार से जुड़ी खबरें उपलब्ध कराते थे और अपनी सूझ-बूझ से धीरे-धीरे उन्होंने नई दुनिया इन्दौर को व्यापार से जुड़े समाचारों में पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। अतुल जी दैनिक भास्कर के व्यापार पृष्ठ को निरन्तर निखारने-सँवारने में जुटे रहे।

व्यापार जगत से जुड़ी खबरों की वजह से भास्कर को व्यापारी वर्ग में काफी पसन्द किया जाने लगा। हॉट लाइन और अन्य सुविधाएँ बढ़ने पर अतुलजी ने मुम्बई और दिल्ली बाजारों से खुलने वाले भाव-ताव आदि का कवरेज भी प्रबन्धन के निर्देश पर शुरू किया। उनकी लगनशीलता को देखते हुए भास्कर प्रबन्धन ने एक नया पद व्यापार प्रतिनिधि का बनाया। समाचार-पत्रों की दुनिया से जुड़े वरिष्ठ सदस्य आज भी दावा करते हैं कि इस के पहले तक प्रदेश के किसी भी समाचार पत्र में व्यापार प्रतिनिधि का पद नहीं हुआ करता था। विभिन्न समाचार पत्रों में लम्बे समय से व्यापार की रिपोर्टिंग से जुड़े प्रतिनिधि आज भी अतुलजी का स्मरण करना नहीं भूलते। पुराने व्यापार प्रतिनिधि बेहिचक अतुलजी को अपना गुरू स्वीकारते हैं। काम की अनूठी शैली और कुछ नया व लीक से हटकर करने की ललक की वजह से दैनिक सांध्य प्रकाश भोपाल ने भी अपने व्यापार पृष्ठ के लिए अतुलजी की कई वर्षों तक सेवाएँ लीं। गुजरात और मुम्बई से निकलने वाले व्यापार नामक समाचार-पत्र के लिए भी अतुलजी ने मध्यप्रदेश के बाजार के मूड को लेकर वर्षों तक समीक्षा लिखी। तीन जनवरी 1933 को जन्में अतुलजी नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा के रहने वाले थे। आचार्य रजनीश के साथ पढ़े-बढ़े अतुलजी का अपने इस मित्र के साथ ही घर छोड़कर निकल जाने का इरादा था। मगर पारिवारिक बन्धनों से मुक्ति मिलना उन दिनों आसान नहीं था। जबलपुर में सरकारी नौकरी लग जाने के बाद मन नहीं लगा और उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। वर्ष 1966 में विवाह हो जाने के बाद वे भोपाल आ गए और स्ट्रा प्रोडक्ट (पुट्ठा मिल) में प्रबन्धक हो गये लेकिन अलहदा मिजाज की वजह से यह नौकरी भी उन्हें रास नहीं आयी। पुट्ठा मिल को अलविदा कह वे पत्रकारिता के क्षेत्र में कूद गये और फिर दुनिया से विदाई तक उनकी कलम नहीं रुकी 4 अक्टूबर, 1987 को हृदयगति रुकने से अतुल जी के जीवन की यात्रा थम गई। जीवन के थमने तक उन्होंने काम किया। अस्थमा के रोगी रहे अतुल जी को जानने वाले उनकी जीवटता के कायल थे। संयोगवश अतुलजी के पिताजी ने भी कुछ समय तक दैनिक भास्कर भोपाल में काम किया था। अतुल जी के ज्येष्ठ पुत्र संजीव भी भोपाल में सक्रिय पत्रकार हैं।

भारत आर्थिक महाशक्ति बनने के रास्ते परः हरिवंश

-प्रो. संजय द्विवेदी

वर्धाः राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारत आर्थिक महाशक्ति बनने के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि आर्थिक समृद्धि प्राप्त होने पर भारत का भविष्य उज्जवल होगा। श्रम, उद्योग और उद्यम ही भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा। हरिवंश बुधवार को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में आयोजित 'भावी दुनिया में भारत' विषय पर विशेष व्याख्यान दे रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. कृष्ण कुमार सिंह ने की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आगे कहा कि बिना आर्थिक रूप से सफल हुए कोई भविष्य नहीं है। यह अस्तित्व से जुड़ा सवाल और पहली बुनियादी सोच है। भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। इतिहास में हम समृद्ध थे, यही धारणा इस कथन के पीछे थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमें 13.5 आर्थिक विकास की दर से आगे बढ़ना होगा। इससे हम आर्थिक रूप से समृद्ध तो होंगी ही, हमारी सारी समस्याएं भी हल होंगी। कोविड़ विपदा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस विपदा का सामना करने के लिए भारत ने महज 9 महीने के भीतर दो-दो टीके बनाए। हममें क्षमता है यह दिखा दिया। अर्जुन के लक्ष्य की तरह हमारी नजर अपने ध्येय को साकार करने के लिए होनी चाहिए। मिलकर काम करने से हम नये भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज हम तेज उभरती अर्थव्यवस्था में से एक हैं। यदि हम 2024 तक 55 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था हासिल करते हैं तो इससे रोजगार में निश्चित ही वृद्धि होगी। उन्होंने भविष्य के भारत में युवाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे भारत में स्टार्टअप का माहौल बना हुआ है। युवा रोजगार सृजन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी मेधा अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों में सेवाएं दे रही हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य एल-1 के कारण हम दुनिया में अग्रणी हो रहे हैं। इस क्षेत्र ने 20 हजार करोड़ से भी अधिक का आर्थिक योगदान दिया है। कृषि उद्योग, खिलौना उद्योग में भी हमारा निर्यात बढा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुनिया को बदल देगा। इसमें अभिशाप भी है और अवसर भी। सेमी-कंडक्टर निर्माण में भी हम अग्रसर हो रहे है। विकास-विकास और विकास ही लक्ष्य हो तब हम आने वाले दिनों में दुनिया में अग्रणी होंगे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया वे अपना राष्ट्रीय लक्ष्य तय करें। अपने भाषण में उन्होंने महात्मा गांधी, चाणयक्य, मार्क्स, बसवेश्वर, स्वामी विवेकानंद से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी आदि भारत के निर्माताओं के प्रेरक उद्धरणों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राजनीति, कौशल भारत आदि विषयों पर अपने विचार रखे। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रो. कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि हमें अपनी विरासत और संस्कृति का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना है। हमें नेतृत्वकारी भूमिका निभानेवाले लोगों के कार्य सामने रखने होंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम की यात्रा शक्ति पथ पर ले जाती है तो भारत की यात्रा मुक्ति पथ पर ले जाती है। विषय परिवर्तन करते हुए शिक्षा विभाग के अधिष्ठाता प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर ने कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया में पहुचाया है। हमारी चिंतन परंपरा दुनिया को भविष्य का रास्ता दिखाती है। स्वागत भाषण जनसंचार विभाग के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के संयोजक प्रो. कृपाशंकर चौबे ने किया। इस अवसर पर कुलपति प्रो. सिंह ने हरिवंश का शॉल, सूतमाला एवं विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। (जगत फीचर्स)

गरीब जनता को सूदखोरों के कर्ज में धकेलना चाहती है भाजपा- बब्बू यादव, नेता प्रतिपक्ष

-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. सागर। नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह यादव ने नगर निगम की कार्यवाही को असंसदीय ठहराते हुए हुए कहा कि निगम परिषद को आम जनता की समस्याओं और शहर के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। वह तो अपनी पार्टी के सूदखोरों को गरीबों का खून चूसने का लाइसेंस देने की चिंता में डूबी हुई है। उपनेता प्रतिपक्ष ताहिर खान कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सूदखोरों से पूरे देश की जनता को मुक्ति दिलाई थी वहीं दूसरी तरफ भाजपा एक बार फिर गरीब और मजबूर जनता को सूदखोरों की जाल में धकेलना चाहती है, जो कांग्रेस को कतई मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्षद दल में शामिल नीलोफर चमन अंसारी, सुलेखा राकेश राय, शिवशंकर गुड्डू यादव, अशोक साहू चकिया, रोशनी वसीम खान, रिचा सिंह, शशि महेश जाटव ने कहा है कि भाजपा शासित नगर निगम परिषद द्वारा अपनी साधारण सभा में जनहित और शहर विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं किया जाना शहर की जनता के साथ खुला धोखा है जिसके लिए कांग्रेस पार्षद दल सदन की बात को सड़क पर लाकर आम जनता के सामने भाजपा की कलई को खोलेगा।

कांग्रेस पार्षदों ने किया सम्मेलन का बहिष्कार

नगर निगम परिषद में सत्ता पक्ष भाजपा के पार्षदों और निगम अध्यक्ष के बीच लगातार चलती तनातनी और हंगामा को देखकर नेता प्रतिपक्ष बाबूसिंह यादव और कांग्रेस पार्षदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष द्वारा हंगामा शांत कर चर्चा शुरू करने की बात पर कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि बीजेपी के पार्षद आपस में ही झगड़ रहे है। पहले आप लोग आपस के अपने मुद्दे तो सुलझा लो, हम फिर बात करेंगे। जिसके तुरंत बाद ही कांग्रेस पार्षदों ने सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा कर सभाकक्ष से बाहर चले गए। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों को रोकने की कोशिश भी की गई लेकिन वे नहीं माने। (जगत फीचर्स)

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)